ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 2, March 2023

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

वर्तमान भारत में दबाव समूह की बढ़ती भूमिका

Dr. Rohit Kumar Meena

Assistant Professor, Govt. PG College, Gangapur City, Sawai Madhopur, Rajasthan, India

सार:

- दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह है जो अपने साझा हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करता है। यह सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करता है।
- दबाव समूहों को हित समूह या निहित समूह भी कहा जाता है। वे राजनीतिक दलों से अलग होते हैं, क्योंकि वे न तो चुनाव लड़ते हैं और न ही राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। वे विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों से जुड़े होते हैं और उनकी गतिविधियाँ सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा और संवर्धन तक ही सीमित होती हैं।
- दबाव समूह कानूनी और वैध तरीकों जैसे लॉबिंग, पत्राचार, प्रचार, प्रसार, याचिका, सार्वजनिक बहस, अपने विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखने आदि के माध्यम से सरकार में नीति-निर्माण और नीति कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

I. परिचय

- दबाव समूहों द्वारा प्रयुक्त तकनीकें
- दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तीन अलग-अलग तकनीकों का सहारा लेते हैं।
- चुनाव प्रचार: सार्वजनिक पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना जो संबंधित दबाव समूह के हितों के प्रति अनुकूल रुख रखते हों।
- लॉबिंग: सार्वजनिक अधिकारियों को, चाहे वे शुरू में उनके प्रति अनुकूल हों या नहीं, उन नीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए राजी करना जो उनके अनुसार उनके हितों के लिए सबसे अधिक लाभदायक साबित होंगी।
- प्रचार-प्रसार: जनमत को प्रभावित करना और इस प्रकार सरकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव प्राप्त करना, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार काफी हद तक जनमत से प्रभावित होती है।
- दबाव समूहों की विशेषताएं
- कुछ हितों के आधार पर: प्रत्येक दबाव समूह कुछ हितों को ध्यान में रखते हुए खुद को संगठित करता है और इस प्रकार राजनीतिक प्रणालियों में सत्ता की संरचना को अपनाने की कोशिश करता है।
- आधुनिक और पारंपरिक साधनों का उपयोग: वे राजनीतिक दलों को वित्तपोषित करने, चुनाव के समय अपने करीबी उम्मीदवारों को प्रायोजित करने और नौकरशाही को भी संतुष्ट रखने जैसे तरीकों को अपनाते हैं। उनके पारंपरिक साधनों में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए जाति, पंथ और धार्मिक भावनाओं का शोषण करना शामिल है।[1,2]
- संसाधनों पर बढ़ते दबाव और मांग के परिणामस्वरूप: संसाधनों की कमी, समाज के विभिन्न और प्रतिस्पर्धी वर्गों द्वारा संसाधनों पर दावे और प्रतिदावे के कारण दबाव समूहों का उदय होता है।
- राजनीतिक दलों की अपर्याप्तता: दबाव समूह मुख्य रूप से राजनीतिक दलों की अपर्याप्तता का परिणाम हैं।
- बदलती चेतना का प्रतिनिधित्व करें: उदाहरण के लिए खाद्य उत्पादन या औद्योगिक वस्तुओं में वृद्धि व्यक्तियों और समूहों के दुनिया को देखने के तरीके में बदलाव लाती है। उत्पादन में ठहराव भाग्यवाद की ओर ले जाता है लेकिन उत्पादन में वृद्धि मांगों, विरोधों और नए दबाव समूहों के गठन की ओर ले जाती है।
- दबाव समूहों के प्रकार
- संस्थागत हित समूह: ये समूह औपचारिक रूप से संगठित होते हैं जिनमें पेशेवर रूप से कार्यरत व्यक्ति शामिल होते हैं। वे सरकारी मशीनरी का हिस्सा होते हैं और अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इन समूहों में राजनीतिक दल, विधायिकाएँ, सेनाएँ, नौकरशाही आदि शामिल हैं। जब भी ऐसा कोई संगठन विरोध करता है तो वह संवैधानिक तरीकों से और नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसा करता है।
    - उदाहरण: आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, राज्य सिविल सेवा एसोसिएशन, आदि।
- एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप: ये संगठित विशेषीकृत समूह हैं जो हितों की अभिव्यक्ति के लिए बनाए गए हैं, लेकिन सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इनमें ट्रेड यूनियन, व्यापारियों और उद्योगपतियों के संगठन और नागरिक समूह शामिल हैं।
    - भारत में एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप के कुछ उदाहरण हैं बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन जैसे AITUC (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस), शिक्षक संघ, छात्र संघ जैसे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) आदि।

- एनोमिक हित समूह: एनोमिक दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य समाज से राजनीतिक व्यवस्था में कमोबेश स्वतःस्फूर्त हस्तक्षेप से है, जैसे दंगे, प्रदर्शन, हत्याएं आदि।
- गैर-सहयोगी हित समूह: ये रिश्तेदारी और वंश समूह तथा जातीय, क्षेत्रीय, स्थिति और वर्ग समूह हैं जो व्यक्ति, परिवार और धार्मिक प्रमुखों के आधार पर हितों को व्यक्त करते हैं। इन समूहों की संरचना अनौपचारिक होती है। इनमें जाति समूह, भाषा समूह आदि शामिल हैं।
- भारत में दबाव समूह
- व्यावसायिक समूह – फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन (एफएआईएफडीए), आदि
- ट्रेड यूनियनें – अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी), भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)
- व्यावसायिक समूह – भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ (एआईएफयूसीटी)
- कृषि समूह- अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, आदि
- छात्र संगठन- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), अखिल भारतीय छात्र महासंघ (एआईएसएफ), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई)
- धार्मिक समूह – राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), जमात-ए-इस्लामी, आदि।
- जाति समूह – हरिजन सेवक संघ, नादर जाति संघ, आदि[3,4]
- भाषाई समूह – तमिल संघ, आंध्र महासभा, आदि
- जनजातीय समूह - नागालैंड में राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (एनएससीएन), त्रिपुरा में जनजातीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक (टीएनयू), यूनाइटेड मिजो फेडरल ऑर्ग, असम में जनजातीय लीग, आदि।
- विचारधारा आधारित समूह - नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला अधिकार संगठन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आदि।
- असामाजिक समूह - नक्सली समूह, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), दल खालसा, आदि।
- दबाव समूहों के कार्य, भूमिका और महत्व
- रुचि अभिव्यक्ति: दबाव समूह लोगों की मांगों और जरूरतों को निर्णयकर्ताओं के ध्यान में लाते हैं। जिस प्रक्रिया से लोगों के दावे स्पष्ट और स्पष्ट होते हैं, उसे रुचि अभिव्यक्ति कहते हैं।
- राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट: दबाव समूह राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट हैं क्योंकि वे राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति लोगों के रुझान को प्रभावित करते हैं। ये समूह लोगों और सरकार के बीच दो-तरफ़ा संचार लिंक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- दबाव समूह विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न केवल हितों की अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में, बल्कि वांछित कानूनों को पारित कराने या सरकार के कानूनों और नीतियों में संशोधन के लिए विधायकों के साथ पैरवी करने में सक्रिय एजेंसियों के रूप में भी।
  - विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणापत्र तैयार करने से लेकर विधायकों द्वारा कानून पारित करने तक, दबाव समूह नियम-निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं।
- दबाव समूह और प्रशासन: दबाव समूह प्रशासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। नौकरशाही के साथ पैरवी करके, दबाव समूह आमतौर पर नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं।
- न्यायिक प्रशासन में भूमिका: दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हित समूह अक्सर सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतों के निवारण के साथ-साथ किसी विशेष निर्णय या नीति को असंवैधानिक घोषित करवाने के लिए न्यायालय तक पहुँच चाहते हैं।
- दबाव समूह जनमत निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं । प्रत्येक दबाव समूह लगातार उन सभी कानूनों, नियमों, निर्णयों और नीतियों का मूल्यांकन करने में लगा रहता है जिनका उसके हितों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह हमेशा अपने सदस्यों के सामने ही नहीं बल्कि आम जनता के सामने भी पक्ष-विपक्ष रखता है ताकि लोकप्रिय समर्थन प्राप्त किया जा सके और साथ ही सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया जा सके।
  - वे सूचना अभियान चलाकर, बैठकें आयोजित करके, याचिका दायर करके, अपने लक्ष्यों और अपनी गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनमें से अधिकांश समूह मीडिया को इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
- दबाव समूह सरकार की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। प्रभावित समूहों के साथ परामर्श एक स्वतंत्र समाज में निर्णय लेने का तर्कसंगत तरीका है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाकर सरकार को अधिक कुशल बनाता है - इन समूहों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह सरकारी नीति और कानून की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करती है।

- उदार लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए स्वतंत्र रूप से संचालित दबाव समूह आवश्यक हैं।
    - वे सरकार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ संस्था के रूप में कार्य करते हैं;
    - वे राजनीतिक शक्ति के फैलाव में सहायता करते हैं;
    - वे शक्ति के संकेन्द्रण को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिभार प्रदान करते हैं।
- दबाव समूह नई चिंताओं और मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं, जिससे सामाजिक प्रगति में मदद मिलती है और सामाजिक ठहराव को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, महिला और पर्यावरणवादी आंदोलन।
- दबाव समूह व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों और मांगों के लिए 'सुरक्षा-वाल्व' निकास उपलब्ध कराकर सामाजिक सामंजस्य और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाते हैं ।
- दबाव समूह सरकार की खराब नीतियों और गलत कामों को उजागर करके विपक्षी राजनीतिक दलों के काम में सहायक होते हैं। दबाव समूह इस तरह मतदाताओं के प्रति निर्णयकर्ताओं की जवाबदेही में सुधार करते हैं ।
- दबाव समूह लोगों को शिक्षित करने, डेटा संकलित करने और नीति निर्माताओं को विशिष्ट जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं, इस प्रकार वे सूचना के अनौपचारिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। राजनीति में कई समूहों की सक्रिय रचनात्मक भागीदारी सामान्य हितों को व्यक्तिगत समूह हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है।
- दबाव समूहों की कमियाँ
- संकीर्ण स्वार्थी हित: पश्चिम के विकसित देशों में दबाव समूहों के विपरीत, जहाँ ये हमेशा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों आदि की रक्षा के लिए संगठित होते हैं, भारत में ये समूह धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय मुद्दों के इर्द-गिर्द संगठित होते हैं। कई बार जाति और धर्म के कारक सामाजिक-आर्थिक हितों को ग्रहण कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि राजनीतिक प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करने के बजाय, वे संकीर्ण स्वार्थी हितों के लिए काम करने लगते हैं।[5,6]
- सत्ता का दुरुपयोग: दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालने के बजाय, राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उपकरण और औजार बन जाते हैं।
- अस्थिरता: अधिकांश दबाव समूहों का स्वायत्त अस्तित्व नहीं होता; वे अस्थिर होते हैं और उनमें प्रतिबद्धता की कमी होती है, उनकी वफ़ादारी राजनीतिक स्थितियों के साथ बदलती रहती है जिससे आम कल्याण को ख़तरा होता है। वे कई बार हिंसा जैसे असंवैधानिक साधनों का सहारा लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 1967 में शुरू हुआ नक्सलवादी आंदोलन इसका एक उदाहरण है।
- उग्रवाद का प्रचार करना: दबाव समूह अनिर्वाचित उग्रवादी अल्पसंख्यक समूहों को सरकार पर बहुत अधिक प्रभाव डालने की अनुमति दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अलोकप्रिय परिणाम हो सकते हैं।
- दबाव समूहों को अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अपरिहार्य और सहायक तत्व माना जाता है। समाज अत्यधिक जटिल हो गया है और व्यक्ति अपने हितों को अपने दम पर आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्हें अधिक सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने के लिए अन्य साथियों के समर्थन की आवश्यकता होती है; इससे सामान्य हितों पर आधारित दबाव समूहों को बढ़ावा मिलता है।
- लोकतांत्रिक राजनीति में परामर्श, बातचीत और कुछ हद तक सौदेबाजी की राजनीति भी शामिल होती है। इसलिए, सरकार के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन के समय इन संगठित समूहों से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है।

II. विचार-विमर्श

दबाव समूह उन अंतर्निहित शक्तियों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं जिनके माध्यम से संगठित समाजों में, विशेष रूप से लोकतंत्रों में राजनीतिक शक्ति को संगठित और लागू किया जाता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सत्तावादी व्यवस्था वाले समाज में उनका पूर्ण रूप से अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक अधिनायकवादी व्यवस्था में भी ऐसे समूह मौजूद होते हैं, हालाँकि वे अत्यधिक सीमित होते हैं और इस प्रकार "केवल राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के साधन के रूप में काम करते हैं, या वे निर्णयों को वैध बनाने के लिए सरकार के मुखौटे का हिस्सा बन सकते हैं।

दबाव समूह – कार्य

संभवतः भागीदारी की डिग्री में सीमांकन की एक रेखा बनी रहती है। एक बहुलवादी समाज, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, दबाव समूहों के अस्तित्व को मान्यता देता है। यह उन्हें 'आधिकारिक प्रशासन' से बाहर गतिविधि के प्रमुख मार्ग बनाने की सीमा तक व्यापक संभव भागीदारी सुनिश्चित करता है। दूसरी ओर, एक अधिनायकवादी व्यवस्था उन्हें अपने हित के अनुकूल एक विशेष दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है और अनुमति देती है।

1. प्रत्येक समाज में, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, हित समूह सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हुए बिना तथा देश पर शासन करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेने से इनकार करके, वांछित दिशा में सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
2. दबाव समूह अनुकूल नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक व्यवस्था चाहते हैं। वे अपनी गतिविधियों के स्वरूप को समायोजित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह सरकारों के औपचारिक संवैधानिक ढांचे से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि सरकारी तंत्र के भीतर प्रभावी शक्ति के वितरण से प्रभावित होता है। इस प्रकार, समूह राजनीति का स्वरूप सरकारी संरचनाओं, गतिविधियों और दृष्टिकोणों

के परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होता है, जो उनके हित के दायरे या तीव्रता के अनुसार होता है। दूसरे शब्दों में, समूह नीतियों का स्वरूप और प्रकृति संरचना और प्रशासनिक एजेंसियों, राजनीतिक संगठन की गतिविधियों और उनके प्रति सरकारी एजेंसियों के दृष्टिकोण से निर्धारित होती है।

3. सरकारी ढांचे के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी को राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन का कार्य प्रशासन की केंद्रीय शाखा को सौंपा जाता है, तो दबाव समूह राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और सुव्यवस्थित स्थिति प्राप्त कर सकता है।
4. एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश में, समूहों की सर्वोच्च इकाइयाँ राष्ट्रीय राजधानी में होती हैं। लेकिन संघीय शासन प्रणाली वाले देश में (जहाँ सत्ता विकेन्द्रित और स्थानीयकृत होती है), कई समूहों की स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी इकाइयाँ होती हैं।[7,8]

दबाव समूह – राजनीति को प्रभावित करना

भारत में दबाव समूहों के प्रभाव का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बिंदु प्रासंगिक हैं।

1. दबाव समूहों की राजनीति सरकारी गतिविधि के चैनलों से निर्धारित होती है। हमें उस जगह पर ध्यान देना चाहिए जहां वास्तव में निर्णय लिए जाते हैं। इसी वजह से समूह अपना ध्यान विधायिका और कार्यपालिका पर केंद्रित करते हैं। जनमत बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाते हैं और चुनावों में 'पसंदीदा' उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया जाता है।
2. जब संसद और मंत्रिमंडल की एजेंसियां नौकरशाही और प्रशासन की अन्य छोटी शाखाओं को अपना अधिकार सौंपती हैं, तो दबाव समूह इस हद तक अपना प्रभाव डाल देते हैं कि सिविल सेवाओं का तटस्थ चरित्र भी गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है।
3. दबाव समूहों के प्रति प्रशासनिक एजेंसियों का रवैया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी, अगर लोकप्रिय मंत्री और विधायी सीटों पर बैठे निर्वाचित प्रतिनिधि इन समूहों की मांगों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, तो उन्हें सरकार तक अपनी पहुँच का एहसास होता है। इसके विपरीत, जब नेतृत्व एक अधिनायकवादी या पारंपरिक या रूढ़िवादी प्रकार का होता है जो किसी एक प्रमुख राजनीतिक दल या सैन्य जुंटा में किसी विशेष गुट के नुकसान के लिए काम करता है, तो समूहों में असंतोष की भावना होती है और वे अधिक अस्पष्ट चैनलों के माध्यम से काम करना शुरू कर देते हैं।

दबाव समूह – वर्गीकरण

दबाव समूहों का अध्ययन सटीक नामकरण के कार्य और प्रक्रियात्मक और मूल चरित्र की अन्य समस्याओं से घिरा हुआ है। सभी समूह एक जैसे नहीं होते, हालाँकि उन्हें इस तरह से पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ निहित स्वार्थों या किसी विशेष सामाजिक या आर्थिक समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें एक दूसरे के लिए कुछ प्रकार की वस्तुनिष्ठ विशेषताएँ होती हैं; अन्य किसी विशेष बिंदु के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, चाहे उनकी वस्तुनिष्ठ विशेषताएँ कुछ भी हों।
ये समूह विभिन्न प्रकार के हैं –

1. उद्देश्य की दृष्टि से स्वार्थी एवं परोपकारी;
2. कार्यकाल के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक; तथा सत्ता की स्थिति के तथ्य को ध्यान में रखते हुए औपचारिक या अनौपचारिक नौकरशाही संगठन।

इसी तरह, ये समूह विधायी निकायों या समग्र रूप से मतदाताओं पर अपने प्रयासों के संकेन्द्रण के मामले में एक दूसरे से भिन्न हैं। जब हम किसी विशेष नीति पर दबाव की राजनीति के कार्यात्मक प्रभाव की जांच करते हैं तो भी अंतर दिखाई देते हैं और यही कारण है कि कुछ समूह अक्सर अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं जबकि अन्य ऐसा करने में विफल हो जाते हैं।

दबाव समूह – भूमिकाएँ

कुल मिलाकर, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ राज्य प्रतिनिधि लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण के आदर्शों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना ज़रूरी है।[9]

1. संगठित हित समूह हर राजनीतिक समुदाय में सक्रिय होते हैं, खासकर एक प्रतिनिधि सरकार में जो समाज सेवा राज्य के आदर्श को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन एक हद तक अंतर यह है कि वे एक गरीब और पिछड़े देश से अलग एक समृद्ध और खुशहाल समाज में अधिक विविध और सक्रिय होते हैं।
2. लेकिन इस हद तक भेदभाव के बावजूद, यह निश्चित है कि पश्चिमी लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में आधुनिकीकरण के कारक द्वारा उनका महत्व बढ़ जाता है जो कार्यात्मक भेदभाव की मशीन में स्नेहक के रूप में कार्य करता है। श्रम विभाजन और कार्यात्मक विशेषज्ञता के रूप में समाज का बहुआयामी चरित्र इसे बहुत बड़ी संख्या में हितों में विभाजित करता है, जिससे समूहों से बना एक सामाजिक संगठन संभव हो जाता है।
3. जब राज्य कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रति प्रतिबद्ध होता है, तो वह सामाजिक समूहों को राजनीति में अधिक हिस्सेदारी प्रदान करता है और इस तरह उन्हें अधिक हद तक संगठित करता है। साथ ही, जब राज्य नियोजन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र

में सकारात्मक भूमिका की नीति अपनाता है, तो वह खुद को ऐसे समूहों की सहायता और सलाह पर अधिक से अधिक निर्भर बनाता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ये समूह एक अधिनायकवादी देश में पूरी तरह से अस्तित्वहीन हैं। वे समाज की अत्यधिक बहुलवादी संरचना में अपेक्षाकृत बड़े प्रतीत होते हैं, जिसमें सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को मान्यता देता है और अत्यधिक एकात्मक प्रणाली में छोटे होते हैं, जहां शीर्ष पर तानाशाह खुद को राज्य के साथ पहचानता है। इसलिए, हित समूहों की भूमिका तब भी स्पष्ट है, जब न्याय की केन्द्रीयता और नियमन सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण की सभी संस्थाओं को सूचित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विविध समूहों को देश के राजनेताओं, राजनेताओं और अन्य नेताओं के साथ विशेष संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र रूप से अंकुरित होने और प्रगति करने की अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर, अंतर की बात यह है कि जहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रवाह की प्रमुख दिशा समूहों से सरकार की ओर होती है, वहीं एक अधिनायकवादी व्यवस्था में यह ठीक इसके विपरीत होता है। उपरोक्त से, यह निष्कर्ष निकलता है कि एक बहुलवादी समाज वाला एक लोकतांत्रिक राज्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया और गतिविधि तक पहुँच और इसमें संगठित हित समूहों की प्रभावी भागीदारी के लिए कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है। जीवन की ऐसी स्थिति अन्य हितों के साथ-साथ राजनीति में भाग लेने के लिए कमज़ोर हितों को भी प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार यह हर समूह के चरित्र को कुछ हद तक, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, राजनीतिक बना देता है। इसका परिणाम समाज की संपूर्ण समूह संरचना का राजनीतिकरण होता है। जैसा कि रोमन कोल्कोविच कहते हैं: "बहुलवादी प्रणालियों में, हम राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए हित समूहों के विचार और वास्तविकता को केंद्रीय रूप से स्वीकार करने लगे हैं। उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक लेन-देन में एक महत्वपूर्ण गुट माना जाता है जिसमें राजनीतिक नेतृत्व, हेरफेर, या विभिन्न हित समूहों की मांगों को समायोजित करता है। एक अधिनायकवादी सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में, हालांकि, एक एकल पार्टी राजनीतिक और सामाजिक प्राधिकरण के संबंध में आधिपत्य का दावा करती है, हित समूह की अवधारणा को कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, एकल पार्टी ऐसी विशेषवादी संस्थाओं के अस्तित्व को नकारती है और उनके उभरने की संभावनाओं को अभिशाप के रूप में देखती है।

संस्थागत दबाव समूह

संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में, दबाव मुख्य रूप से कार्यकारी शाखा पर केन्द्रित होता है, जिसका सीधा सा कारण यह है कि संसद मंत्रियों के हाथों में एक उपकरण की तरह रहती है, जो बदले में अपने स्थायी अधिकारियों के हाथों में एक उपकरण की तरह होते हैं।[10]

1. समकालीन सामाजिक और आर्थिक नीतियों की प्रकृति इतनी तकनीकी हो गई है कि 'आम' संसद, मंत्रिस्तरीय कार्यालयों के आवरण के पीछे रखी गई 'विशेषज्ञ' नौकरशाही से मेल नहीं खाती। इसलिए, उचित स्थान जहाँ वास्तव में निर्णय लिए जाते हैं, वह 'खुली संसद' नहीं बल्कि 'बंद विभाग' है और इस तरह, दबाव समूह प्रशासन की 'बंद' शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।
2. हालांकि, यह विधायिका के सदस्यों के माध्यम से नीति-निर्माण पर प्रभाव डालने की संभावना को समाप्त नहीं करता है, जो प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव रखने, निजी प्रतिनिधित्व करने और अपने प्रतिष्ठित संपर्कों के स्रोत का उपयोग करके अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, कई समूह चुनावी मुकाबलों के समय दान देकर या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करके किसी राजनीतिक दल के साथ गुप्त संबंध बनाए रखते हैं। वे एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में सत्ता के दोलन के खतरों से खुद को बचाने के लिए राजनीतिक तटस्थता का एक रूप प्रस्तुत करते हैं।
3. इस प्रकार, हित समूह पहले पार्टी में और उसके माध्यम से संसद में अपने अभियोजकों को रखने का प्रयास करते हैं, और चूंकि संसद की शक्तियों को हर प्रकार की सरकार में कार्यपालिका द्वारा हड़प लिया गया है, इसलिए वे नीति-निर्माण की प्रभावी शक्ति में हिस्सा पाने के लिए मंत्रियों और सिविल सेवकों पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं।

इस अध्ययन ने हाल ही में भारतीय राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राजनीति विज्ञान ने इतिहास और नैतिकता के साथ अपना बहुत-सा संबंध खो दिया है; यह मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के विषयों के अधिक निकट चला गया है। 'राजनीति' का एक नया अर्थ प्रयोग में आया है, जिसके तहत इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों को प्रामाणिक रूप से आवंटित किया जाता है। ऐसा अध्ययन राजनीति को केवल पारंपरिक अर्थ में राज्य और सरकार के विज्ञान के रूप में नहीं मानता है, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। चूंकि ये निर्णय अक्सर समूह संघर्ष के परिणामस्वरूप लिए जाते हैं, इसलिए यह अध्ययन के अपने दायरे को ऐसे सभी समूहों तक फैला देता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यह नया दृष्टिकोण 'वर्णनात्मक', यदि 'व्याख्यात्मक' सिद्धांत नहीं है, के निर्माण के बराबर है, और जिसे कभी-कभी 'अनौपचारिक' राजनीति कहा जाता है, उससे संबंधित है। स्वाभाविक रूप से, इसने तुलनात्मक राजनीति पर साहित्य के भंडार में सामग्री जोड़ी है, और, हालांकि इस दृष्टिकोण को कई 'सीमांत-दिमाग वाले' लेखकों द्वारा सराहा नहीं गया है, संपूर्ण अध्ययन, जिसे अधिक उपयुक्त रूप से 'राजनीतिक समाजशास्त्र' का अध्ययन कहा जाता है, "तुलनात्मक राजनीति अनुसंधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। दूसरे शब्दों में, यह अध्ययन एक नए व्यक्ति की धुरी के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे राजनीतिक

व्यक्ति कहा जाता है, जो आर्थिक व्यक्ति या नैतिक व्यक्ति से अलग है। यह मनुष्य को 'पृथक परमाणु' के रूप में नहीं बल्कि 'समूहों का प्राणी' के रूप में मानता है। इस प्रकार समस्या 'मनुष्य बनाम राज्य' नहीं है जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने एक अत्यंत व्यक्तिवादी दर्शन की नस में निर्दिष्ट किया है; यह 'समूह बनाम राज्य' है जैसा कि उदारवादी व्यक्तिवाद की आधुनिक व्याख्या की तर्ज पर अर्नेस्ट बार्कर ने सुझाया है। जब लोग समूहों में एकजुट होते हैं तो उनके अपने हित होते हैं और वे अपनी सुरक्षा और संवर्धन के लिए 'दबाव' का उपयोग करते हैं, जैसा कि हैगन बताते हैं, समाज में जीवन, इसके सभी चरणों में, 'सक्रिय व्यक्तियों के समूह' में कहा जा सकता है। सामाजिक मूल्यों का आवंटन विभिन्न गतिविधियों द्वारा लिए गए निर्णयों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होता है, हालांकि ऐसे निर्णयों के संबंध में सामान्य प्रवृत्तियों वाले गतिविधि का समूह समूहों के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार, जो निर्णय लेने को निर्धारित करता है वह विभिन्न समूहों और हितों के बीच निरंतर संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है। इस संदर्भ में देखा जाए तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों द्वारा राजनीति की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है। उदाहरण के लिए, एकस्टीन कहते हैं: "यदि हम कहते हैं कि राजनीति में निर्णय लेना शामिल है, निर्णय समूह संघर्ष के परिणामस्वरूप किए जाते हैं, कि समूह हितों के समान ही हैं, कि समूह और हित दोनों ही गतिविधि का समूह हैं, तो हम केवल यही कहते हैं कि राजनीति गतिविधि है।" इस प्रकार, समूह राजनीति का अध्ययन इस विषय के आधुनिकीकरण की दिशा में एक नई लहर की तरह है, और हालांकि अभी और अधिक उपयोगी सिद्धांत आने बाकी हैं, यह निश्चित है कि बर्फ निश्चित रूप से पिघल चुकी है।[2,3]

III. परिणाम

दबाव समूह अनुकूल नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक व्यवस्था चाहते हैं। यह सरकार के औपचारिक संवैधानिक ढांचे से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि सरकारी तंत्र के भीतर प्रभावी शक्ति के वितरण से प्रभावित होता है। प्रभावशाली संगठन या संघ जो विशिष्ट हित को बढ़ावा देने और सरकार या उनके लक्ष्यों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह सरकार के नागरिकों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है, यह व्यक्तियों को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और अपनी रुचि और शिकायतों को आवाज़ देने में सक्षम बनाता है जो किसी भी लोकतंत्र में आवश्यक अधिकार हैं। दबाव समूह लोगों के संगठित समूह होते हैं जो अपने विशिष्ट हित को बढ़ावा देने और अपने हित की पूर्ति के लिए सरकार या निर्णय निर्माताओं पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं।

दबाव समूह गैर-गठबंधन समूह होते हैं और सिस्टम के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष लेकिन शक्तिशाली समूहों के रूप में काम करते हैं। दबाव समूहों के पास सीमित और संकीर्ण केंद्रित क्षेत्र और मुद्दे होते हैं, एक दबाव समूह एक सार्वजनिक निकाय होता है जो राजनीतिक दलों के दायरे से बाहर काम करता है, सरकार बनाता है और सिस्टम के भीतर काम करता है। दबाव समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी और विधायी पर दबाव डालते हैं, जबकि राजनीतिक दल कार्यकारी और विधायी निकायों के कामकाज में समन्वय लाने का प्रयास करते हैं। यह अपनी मांगों को प्रदर्शित करने के लिए पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरीकों का उपयोग करता है, जबकि राजनीतिक दल अपने कर्तव्यों और कार्यों को निष्पादित करने के लिए केवल संवैधानिक साधनों का उपयोग करते हैं।
कीवर्ड - दबाव समूह, प्रशासनिक प्रणाली, राजनीतिक दल, कानून, सार्वजनिक नीति, नागरिक समाज, संकीर्ण डोमेन, सरकार से बाहर, हितों की सुरक्षा, नीति कार्यान्वयन, नीति निर्माण, राजनीतिक भागीदारी, जनमत, चुनाव प्रचार, पैरवी, प्रचार, लोकतंत्र की वकालत, विधायकों को प्रोत्साहित करना, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, राजनीतिक संगठन, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व।

दबाव समूह भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकारी नीतियों और निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं। भारत में दबाव समूहों का इतिहास स्वतंत्रता-पूर्व समय से शुरू होता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए जनता को संगठित किया था। स्वतंत्रता के बाद, दबाव समूहों में उद्योग संघ, ट्रेड यूनियन, पर्यावरण समूह और बहुत कुछ शामिल हो गए, जिनमें से प्रत्येक अपने-अपने एजेंडे की वकालत करता था। ये समूह अक्सर सरकारी कार्यों को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग, विरोध और वकालत जैसी रणनीति का उपयोग करते हैं, जिससे वे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण अभिनेता बन जाते हैं। ऐसे संगठित समूहों के सदस्य कुछ विशिष्ट हितों को लेकर एकजुट होते हैं जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक कारखाने के कर्मचारी अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड यूनियन नामक संगठन में संगठित होते हैं। दबाव समूह लोगों का एक संगठित समूह है जिसका उद्देश्य जनता की राय या सरकार की नीतियों/कार्रवाइयों को प्रभावित करना होता है। इसमें चर्च और धर्मार्थ संस्थाएं, व्यवसाय और व्यापार संघ, ट्रेड यूनियन और पेशेवर संघ, विभिन्न विचारधाराओं के थिंक टैंक आदि शामिल हैं। दबाव समूह का उद्देश्य यद्यपि कुछ दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, कई दबाव समूह अन्य उद्देश्यों के लिए मौजूद हैं और केवल एक माध्यमिक या संबद्ध गतिविधि के रूप में राजनीति में संलग्न हैं।[4,5]

चूंकि दबाव समूह बाहर से सरकार पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए वे चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं। इस अर्थ में,

वे नागरिक समाज का हिस्सा हैं। ये समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लॉबिंग, शोध अभियान, मीडिया अभियान, नीति संक्षिप्त और सर्वेक्षण सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। इसलिए दबाव समूह लोगों और सरकार के बीच संचार के एक चैनल के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे लॉबिंग, पत्राचार, प्रचार, प्रचार, याचिका, सार्वजनिक बहस, अपने विधायकों के साथ संपर्क बनाए रखने आदि जैसे कानूनी या वैध तरीकों से सरकार में नीति-निर्माण और नीति कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

दबाव समूहों के कार्य, भूमिका और महत्व

बहुलवादी तर्क देते हैं कि दबाव समूह की राजनीति लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समूह विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ और कार्य निभाते हैं जो बहुलवादी लोकतंत्र के विचार को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इस संबंध में, एक बहुलवादी, रॉबर्ट डाहल का मानना है कि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट की धारणा पर आधारित है जिसमें व्यक्ति की भूमिका पर जोर दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें से प्रत्येक की एक इच्छा है जिसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए, इस स्थिति में, एकमात्र तरीका जिससे व्यक्ति सफलतापूर्वक हितों को व्यक्त कर सकता है वह दूसरों के साथ मिलकर है। दबाव समूहों की निम्नलिखित भूमिका और कार्य इस प्रकार हैं:
हितों की अभिव्यक्ति: दबाव समूह लोगों की मांगों और जरूरतों को निर्णयकर्ताओं के ध्यान में लाते हैं। जिस प्रक्रिया से लोगों के दावे क्रिस्टलीकृत और व्यक्त होते हैं उसे हितों की अभिव्यक्ति कहा जाता है।
दबाव समूह और प्रशासन: दबाव समूह प्रशासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। नौकरशाही के साथ पैरवी करके, दबाव समूह आमतौर पर नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं।
न्यायिक प्रशासन में भूमिका: दबाव समूह अपने हितों को सुरक्षित रखने और उनकी रक्षा के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हित समूह अक्सर सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतों के निवारण के लिए और साथ ही किसी विशेष निर्णय या नीति को असंवैधानिक घोषित करवाने के लिए न्यायालय तक पहुँच की मांग करते हैं।
वे सूचना अभियान चलाकर, बैठकें आयोजित करके, याचिका दायर करके, अपने लक्ष्यों और अपनी गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनमें से अधिकांश समूह मीडिया को इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह लोगों को शिक्षित करने, डेटा एकत्र करने और नीति निर्माताओं को विशिष्ट जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं, इस प्रकार वे सूचना के अनौपचारिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। राजनीति में कई समूहों की सक्रिय रचनात्मक भागीदारी सामान्य हितों को व्यक्तिगत समूह हितों के साथ समेटने में मदद करती है।

प्रतिनिधित्व:
दबाव समूह उन समूहों और हितों के लिए मुखपत्र प्रदान करते हैं जिनका चुनावी प्रक्रिया या राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि समूह सामान्य के बजाय विशिष्ट से संबंधित होते हैं, समूह विशेष समूहों के विचारों या हितों को स्पष्ट करते हैं और विशिष्ट कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि दबाव समूह औपचारिक प्रतिनिधि प्रक्रिया के लिए एक विकल्प प्रदान करते हैं जिसे कार्यात्मक प्रतिनिधित्व कहा जाता है।

दबाव समूहों का वर्गीकरण[6,7]

भारत में, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर एक बहुलवादी समाज में, विभिन्न क्षेत्रों में कई दबाव समूह काम कर रहे हैं। उन्हें पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
व्यावसायिक दबाव समूह (फिक्की, सीआईआई, ट्रेड यूनियन, किसान संघ, छात्र संघ, आदि) सामाजिक-सांस्कृतिक दबाव समूह (आरएसएस, वीएचपी, जमात-ए-इस्लामी, हरिजन सेवक संघ, तमिल संघ, आदि) संस्थागत दबाव समूह (पुलिस कल्याण संघ, युद्ध विधवा संघ, आदि) असामाजिक दबाव समूह (नक्सली, आदि) तदर्थ दबाव समूह (देश के विभिन्न हिस्सों में आपदाओं के दौरान गठित, आदि) इनके अलावा, भारत में कुछ विचारधारा-आधारित दबाव समूह भी काम कर रहे हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला अधिकार संगठन, आदि। इन सभी दबाव समूहों से, अन्य देशों की तरह, जनता और राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक सेतु और संचार के स्रोत के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाएं।
भारत में दबाव समूहों से जुड़ी हालिया समस्याएं लोकतंत्र

राजनीतिक फंडिंग के कारण राजनीतिकरण और क्रोनी कैपिटलिज्म विभिन्न अवसरों पर असंवैधानिक साधनों और हिंसा का सहारा लेना गैर-संगठित संरचना और शासन की कमी बेहिसाब विदेशी फंडिंग का अर्थव्यवस्था पर अस्थिर प्रभाव पड़ता है वोट बैंक की राजनीति जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव संकीर्ण दृष्टिकोण और लॉबिंग जो असमानता को बढ़ाती है

उग्रवाद का प्रचार करना। भारत में दबाव समूहों की कुल मिलाकर कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। वे कमजोर हैं और सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल को खुले तौर पर अपना समर्थन नहीं देते हैं। वे अधिकारियों और सरकार को नाराज करने से हिचकिचाते हैं। उम्मीद की जाती है कि ये समूह हमेशा अहिंसक रहेंगे और धर्मनिरपेक्ष नीतियों का पालन करेंगे। भारत में दबाव समूह कई कारणों से बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे खुद को एक दूसरे निकाय के रूप में संगठित करने में विफल रहे हैं। उनके पास कोई अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा नहीं है जो नियमित रूप से और जोरदार तरीके से अपने हितों को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। केंद्र में एक पार्टी के प्रभुत्व वाली व्यवस्था भी उनकी धीमी वृद्धि के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। राजनीतिक दल नहीं चाहते कि शक्तिशाली दबाव समूहों द्वारा भी उनके अधिकार को कोई गंभीर चुनौती दी जाए। इतना ही नहीं, बल्कि दबाव समूहों ने भी राजनीतिक दलों के संरक्षण में विकसित होने की कोशिश की है। उनके पास जाने के लिए उन्हें धन मुहैया कराया जाता है और राजनीतिक आकाओं से निर्देश प्राप्त होते हैं। यहां तक कि राजनीतिक दल प्रत्येक दबाव समूह को विभाजित करने और कम से कम ऐसे एक समूह पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं।

फिर वे अपना काम करवाने के लिए मोटे तौर पर नकारात्मक तरीके अपनाते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि ऐसा तरीका सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक है। फिर उनके धीमे विकास का दूसरा कारण यह है कि भारत में दबाव समूहों को व्यक्तिगत विधायक बहुत प्रभावी नहीं लगे हैं। ऐसे प्रत्येक समूह को यह एहसास है कि पार्टी अनुशासन और दलबदल विरोधी कानून के कारण प्रत्येक विधायक को पार्टी लाइन पर ही वोट करना चाहिए। इस प्रकार, पार्टी के साथ संपर्क विकसित किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत विधायक के साथ। दबाव समूहों को यह भी एहसास है कि भारत में नौकरशाही बहुत मजबूत है और उनकी बहुत मदद कर सकती है। लेकिन किसी तरह अब तक ये समूह नौकरशाही को भ्रष्ट करने में विफल रहे हैं। दबाव समूहों में एकता भी नहीं है। वास्तव में, ऐसा कोई समूह नहीं है जो कई गुटों और उप-समूहों में बुरी तरह से विभाजित न हो, जो एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलते हों। कई मामलों में अच्छे नेताओं की भी कमी है। कई मामलों में दबाव समूह के नेता राजनीतिक नेता बनने की कोशिश करते हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दबाव समूह के मूल चरित्र को विफल कर देती हैं। अधिकांश दबाव समूह जैसे ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन आदि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हैं और बिना वित्त के ये प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते हैं।

यह सर्वविदित है कि भारतीय लोकतंत्र एक मौलिक परिवर्तन से गुजर रहा है। इसमें कई बदलाव हुए हैं, जिनमें चुनावी प्रतिस्पर्धा की प्रकृति में प्रणालीगत बदलाव, मध्यम वर्ग के आकार में कई गुना वृद्धि, सोशल मीडिया का प्रवेश और पुरानी पदानुक्रमों का खत्म होना आदि शामिल हैं। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सामाजिक और भौगोलिक विस्तार ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस और अधिक हाशिए पर चली गई है, वाम मोर्चा का पतन हुआ है और राज्य स्तरीय दलों की ताकत में गिरावट आई है। बीजेपी ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया है, जिससे अतीत में विभिन्न मतदान ब्लॉकों के बीच मतभेद कम हुए हैं और साथ ही अन्य सामाजिक दरारें भी कम हुई हैं। इसी तरह, राज्य स्तरीय विशिष्टताएँ जो पिछले दो दशकों में चर्चा में हावी थीं, अब चुनावी विश्लेषणों में कुछ हद तक कम हो गई हैं, खासकर राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेखा को समझने के लिए।

न्यायपालिका की भूमिका

लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च होता है और न्यायपालिका इसकी संरक्षक होती है। लोकतंत्र लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों या प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देता है। शक्तियों का पृथक्करण शासन को तीन शाखाओं में विभाजित करता है: विधायिका कानून बनाती है, जो सार्वजनिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है; कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री करते हैं; और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और उन्हें लागू करती है, संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करती है और अधिकारों की रक्षा करती है। यह पृथक्करण सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। भारत जैसी संसदीय प्रणालियों में, कार्यपालिका और विधायिका अन्योन्याश्रित हैं। न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण जाँच के रूप में कार्य करती है, कानून के शासन को बनाए रखती है और सत्ता के दुरुपयोग से बचाती है, एक संतुलित लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित करती है न्यायपालिका के पास किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई की समीक्षा करने की शक्ति है न्यायिक समीक्षा की यह शक्ति भारत के संविधान को आकार देने और यह सुनिश्चित करने में सहायक रही है कि संविधान के प्रावधान प्रभावी रूप से लागू हों। न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान ने यूएसए के संविधान से अपनाया है। भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा व्यापक है और यह कई तरह के मुद्दों से निपटती है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों के लिए 2017 में अपनी शुरुआत से लेकर 15 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने तक फंडिंग का एक तरीका था। सुप्रीम कोर्ट के पास कई तरह से न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष या विधायिका और कार्यपालिका द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यह अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त विभिन्न रिट जारी करके

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और वन्यजीव संरक्षण के लिए जनहित याचिकाओं का सक्रिय रूप से उपयोग किया है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक रही है, जिसमें निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव का मुकाबला करना शामिल है। ऐतिहासिक निर्णयों ने शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों को भी आगे बढ़ाया है और समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया है, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुआ है।[8,9]

IV. निष्कर्ष

दबाव समूहों को अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सहायक और अपरिहार्य तत्व माना जाता है। समाज अत्यधिक जटिल हो गया है और व्यक्ति अपने हितों को अपने दम पर आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्हें अधिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य साथियों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इससे समान हितों पर आधारित दबाव समूहों का उदय होता है। लंबे समय तक, इन समूहों पर किसी का ध्यान नहीं गया। शुरू में उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक माना जाता था, लेकिन अब राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। लोकतांत्रिक राजनीति परामर्श और बातचीत के माध्यम से राजनीति होनी चाहिए और इसमें कुछ हद तक सौदेबाजी भी शामिल है। इसलिए, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के समय सरकार के लिए इन संगठित समूहों से परामर्श करना बहुत आवश्यक है। दबाव समूह विविध हितों की वकालत करके और संस्थाओं को जवाबदेह बनाकर भारतीय लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हुए, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भारत में दबाव समूहों की गतिविधियों की प्रभावशीलता और वैधता को बढ़ा सकता है।[10]

संदर्भ

1. व्यवसाय समूह - जैसे फिक्की , एसोचेम ,एमओ इत्यादी
2. व्यापार संघ - जैसे AITUC , INTUC , HMS , CITU इत्यादि
3. खेतिहर समूह - जैसे भारतीय किसान यूनियन , ऑल इंडिया किसान सभा , भारतीय किसान सभा इत्यादि
4. छात्र संगठन - जैसे ABVP , NSUI , AISA इत्यादि
5. पेशेवर समितियां - जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन , बार कौंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि
6. धार्मिक संगठन - जैसे आरएसएस , विहिप , जमात - ए - इस्लामी , शिरोमणि अकाली दल इत्यादि
7. जातीय समूह - जैसे हरिजन सेवक संघ , कायस्थ समूह , ब्राह्मण सभा , राजपूत समूह इत्यादि
8. भाषागत समूह - तमिल संघ , नागरी प्रचारिणी सभा , हिंदी साहित्य सम्मेलन इत्यादि
9. आदिवासी संघठन समूह - NSSCN , PLA , JMM , TNU इत्यादि
10. विचारधारा समूह - जैसे अम्बेडकवादी ,गांधीवादी, पर्यावरणवादी इत्यादि नेवल किशोर मौर्य

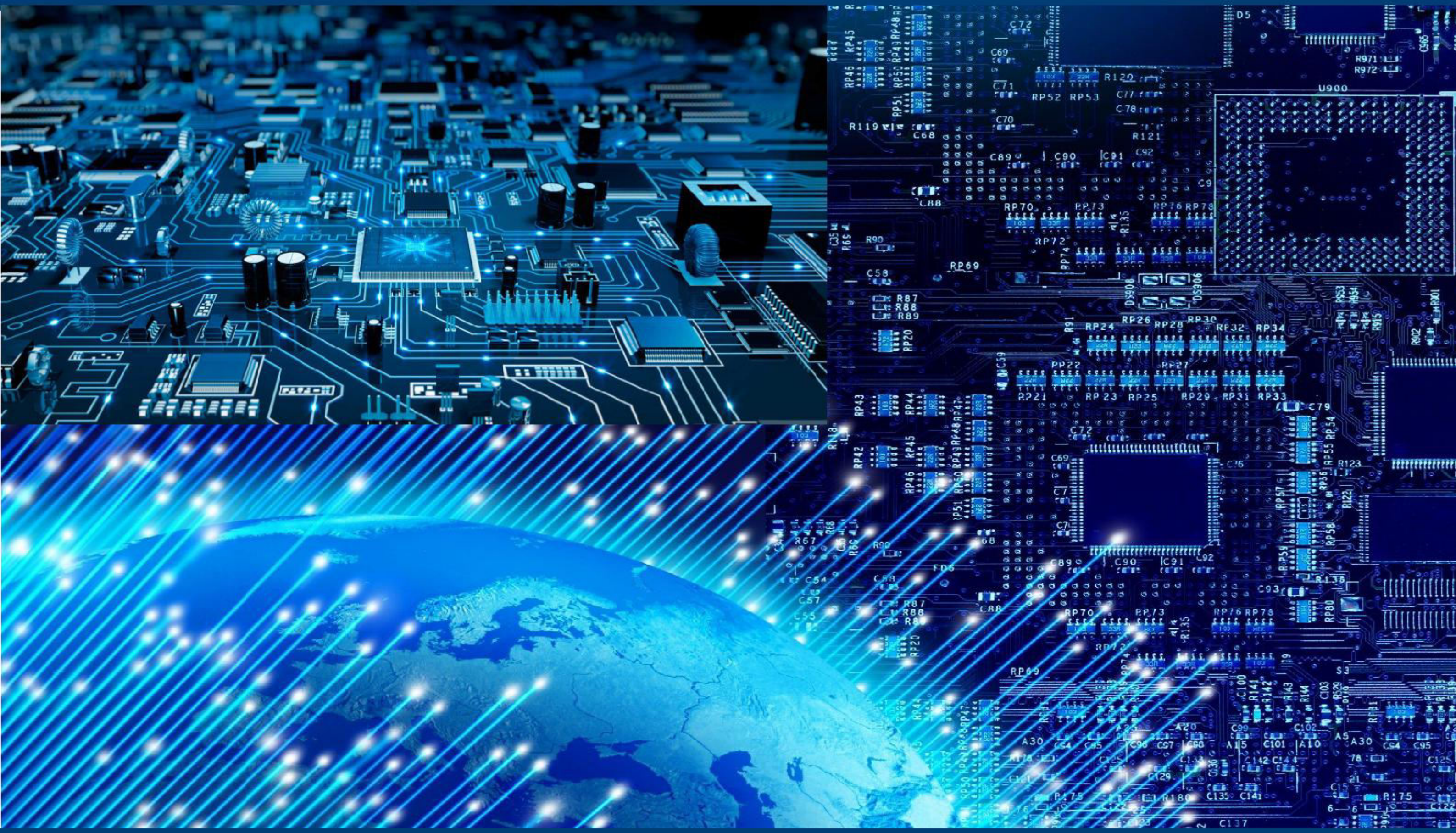

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com